Government of Haryana
Finance Department

हरियाणा सरकार
वित्त विभाग

No. 11/25/2023-1FR/2478

To

1. The Chief Secretary to Government Haryana (Vigilance Deptt.)
   w.r.t. memo no. 02/04/2022-1VII dated 02.12.2022, and
   file bearing CFMS No. 113602 dated 22.11.2022.
2. All Administrative Secretaries to Government Haryana.
3. All Heads of Departments, Statutory Bodies, Boards and Corporations (except Power Utilities).
4. The Registrar General, Punjab and Haryana High Court Chandigarh
5. All the Commissioners of Divisions, Ambala, Karnal, Faridabad, Gurguram, Hisar and Rohtak
6. All Deputy Commissioner and Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana

Dated: 13th February, 2023

Subject: - Departmental Financial (Haryana Amendment) Rules, 2023.

****

Sir/Madam,

Reference on the subject noted above.

2. Please find enclosed herewith copy of notification bearing No. 11/25/2023-1FR/2478 dated 03.02.2023 published in Haryana Government Gazette which pertains to Departmental Financial (Haryana Amendment) Rules, 2023 for your kind perusal and necessary compliance.

3. Government has also decided that:-

a) The Finance Department shall issue instructions regarding procedural modalities and timelines. etc, from time to time.
b) A check list for preparation of estimates so as to ensure that no requisite provision is left out. All provisions including furniture, maintenance of building, fire services, horticulture services etc. should be taken into account. The check list should be finalized by a Committee of Chief Engineers headed by the Engineer-in Chief PWD (B&R) Department and thereafter circulated to all the departments for ensuring that estimates are complete in all respects.
c) The Citizen Resources Information Department shall shortlist appropriate software(s) for monitoring of large scale projects in different departments.

4. Copy of this order is available only through the official website of the Finance Department i.e. finhry.gov.in and not circulated through any other means of communication.

DA : As above.

Special Secretary Finance
for the Addl. Chief Secretary to Govt. Haryana
Finance Department.

Endst. No. 11/25/2023-1FR/2478 Dated: 13th.02.2023

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. Principal Accountant General (Audit), Haryana, Chandigarh.

P.T.O.

3. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, PW (B&R) Department with specific request to make compliance of all relevant provisions as per attached notification as well as on the para 3 (b) mentioned overleaf. It is also requested to take necessary action w.r.t. Order No. 44/135/05-05B&R (W) dated 23.04.2008, as may deem fit.
4. The Additional Chief Secretary to Govt. Haryana, Citizen Resources Information Department with specific request to make compliance of all relevant provisions as per attached notification as well as on the para 3 (c) mentioned overleaf.
5. All the Treasury Officer in Haryana including Treasury Officers, Chandigarh and Tees Hazari, Court, Delhi.
6. The Incharge, Computer Cell (Finance Department) for uploading these instructions on the website of the Finance Department.

Special Secretary Finance
for the Addl. Chief Secretary to Govt. Haryana
Finance Department.

DA : As above.

A copy is forwarded to the Chief Principal Secretary, Principal Secretary and Additional Principal Secretary/Officers on Special Duty/Senior Secretaries/Secretaries/Private Secretaries for information of Hon'ble Chief Minister, Deputy Chief Minister and Ministers of Haryana State.

Special Secretary Finance
for the Addl. Chief Secretary to Govt. Haryana
Finance Department.

DA : As above.

To

The Chief Principal Secretary, Principal Secretary and Additional Principal Secretary/Officers on Special Duty/Senior Secretaries/ Secretaries/Private Secretaries to Hon'ble CM/Deputy CM/Ministers.

U.O. No. 11/25/2023-1FR/2478 Dated: 13.02.2023

A copy is forwarded to the Chief Secretary to Govt. Haryana, Human Resources Department (HR-I Branch) for information and necessary action w.r.t. U.O. No. 13/07/2023-3HR-I dated 01.02.2023.

Special Secretary Finance
for the Addl. Chief Secretary to Govt. Haryana
Finance Department.

DA : As above.

To

The Chief Secretary to Govt. Haryana,
Human Resources Department (HR-I Branch).

U.O. No. 11/25/2023-1FR/2478 Dated: 13.02.2023

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 6–2023] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023 (MAGHA 18, 1944 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 03 फरवरी, 2023

संख्या 11/25/2023-1एफ०आर०/2478.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, विभागीय वित्तीय नियम, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम विभागीय वित्तीय (हरियाणा संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. विभागीय वित्तीय नियम में, नियम 10.6 में, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"**सारणी**

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	जिसे प्रत्यायोजित की गई हैं	सीमा
1.	2.	3.	4.
1.	सभी प्रकार के संकर्मों के निष्पादन हेतु निविदाएं स्वीकार करना	....	**प्रत्येक कार्य के लिए पच्चीस लाख रूपए तक–**
		(i) उप मंडल अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा राशि, अधिकतम पच्चीस लाख रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमनित लागत का पंच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
		(ii) कार्यकारी अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम पच्चीस लाख रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमनित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक किन्तु दस प्रतिशत तक होगी
		(iii) अधीक्षण अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम पच्चीस लाख रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमनित लागत का दस प्रतिशत से अधिक होगी

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	जिसे प्रत्यायोजित की गई हैं	सीमा
1.	2.	3.	4.
2.	सभी प्रकार के संकर्मों के निष्पादन हेतु निविदाएं स्वीकार करना	....	**प्रत्येक कार्य के लिए पच्चीस लाख रूपए से अधिक किन्तु एक करोड़ रूपए तक–**
		(i) कार्यकारी अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा राशि, एक करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक नही होगी
		(ii) अधीक्षण अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम एक करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक किन्तु दस प्रतिशत तक होगी
		(iii) मुख्य अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम एक करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत से अधिक होगी
3.	सभी प्रकार के संकर्मों के निष्पादन हेतु निविदाएं स्वीकार करना	...	**प्रत्येक कार्य के लिए एक करोड़ से अधिक किन्तु तीन करोड़ रूपए तक–**
		(i) अधीक्षण अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम तीन करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक नही होगी
		(ii) मुख्य अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम तीन करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक किन्तु दस प्रतिशत तक होगी
		(iii) विभागाध्यक्ष के अध्यक्ष, के रूप में तथा इसके सदस्यों के रूप में मुख्य अभियंता तथा मुख्य लेखा अधिकारी से मिलकर बनने वाली निविदा आबंटन समिति	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम तीन करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत से अधिक होगी
4.	सभी प्रकार के संकर्मों के निष्पादन हेतु निविदाएं स्वीकार करना	....	**प्रत्येक कार्य के लिए तीन करोड़ रूपए से अधिक किन्तु पांच करोड़ रूपए तक–**
		(i) मुख्य अभियंता	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम पांच करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
		(ii) विभागाध्यक्ष	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम पांच करोड़ रूपए की सीमा के साथ निविदा की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक किन्तु दस प्रतिशत तक होगी
		(iii) विभागाध्यक्ष के अध्यक्ष, के रूप में तथा इसके सदस्यों के रूप में मुख्य अभियंता तथा मुख्य लेखा अधिकारी से मिलकर बनने वाली निविदा आबंटन समिति	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम पांच करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत से अधिक होगी

क्रम संख्या	शक्ति का स्वरूप	जिसे प्रत्यायोजित की गई हैं	सीमा
1.	2.	3.	4.
5.	सभी प्रकार के संकर्मों के निष्पादन हेतु निविदाएं स्वीकार करना	....	**प्रत्येक कार्य के लिए पांच करोड़ रूपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रूपए तक–**
		(i) प्रशासकीय सचिव	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम दस करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
		(ii) अध्यक्ष के रूप में कार्यभारी मन्त्री, इसके सदस्यों के रूप में तथा प्रशासकीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष से मिलकर बनने वाली समिति	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम दस करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का दस प्रतिशत से अधिक होगी
6.	सभी प्रकार के संकर्मों के निष्पादन हेतु निविदाएं स्वीकार करना	...	**प्रत्येक कार्य के लिए दस करोड़ रूपए से अधिक किन्तु पन्द्रह करोड़ रूपए तक–**
		(i) कार्यभारी मन्त्री	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम पन्द्रह करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
		(ii) अध्यक्ष के रूप में मुख्य मन्त्री, इसके सदस्यों के रूप में कार्यभारी मन्त्री, प्रशासकीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष से मिलकर बनने वाली समिति	इस शर्त के अध्यधीन कि न्यूनतम निविदा की राशि, अधिकतम पन्द्रह करोड़ रूपए की सीमा के साथ जारी निविदा की अनुमानित लागत का पांच प्रतिशत से अधिक होगी
7.	सभी प्रकार के संकर्मों के निष्पादन हेतु निविदाएं स्वीकार करना	अध्यक्ष के रूप में मुख्य मन्त्री, इसके सदस्यों के रूप में कार्यभारी मन्त्री, प्रशासकीय सचिव तथा विभागाध्यक्ष से मिलकर बनने वाली समिति	प्रत्येक कार्य के लिए पन्द्रह करोड़ रूपए से अधिक

टिप्पण:–1. उपरोक्त सारणी के अनुसार प्रत्यायोजन सभी सरकारी विभागों पर लागू होगा। सभी स्थानीय निकायों, यानी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के अपने अलग–अलग प्रत्यायोजन होंगे, जैसा कि उनके संबंधित विभागों द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. वैधानिक निकायों, बोर्डों और निगमों (विद्युत उपयोगिताओं को छोड़कर) के मामले में, निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 10 करोड़ रूपये तक की निविदाओं के लिए मौजूदा प्रत्यायोजन के अनुसार होगा। 10 करोड़ रूपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले संकर्मों के लिए, अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री, कार्यभारी मंत्री, प्रशासकीय सचिव तथा संबंधित वैधानिक निकाय, बोर्ड या निगम (सीए, सीईओ या एमडी, जैसी भी स्थिति हो) से मिलकर बनने वाली समिति निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।"।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 03rd February, 2023

No. 11/25/2023-1FR/2478.— In exercise of the powers conferred under clause (2) of article 283 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Departmental Financial Rules in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Departmental Financial (Haryana Amendment) Rules, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Departmental Financial Rules, in rule 10.6, for serial numbers 1, 2, 3, 4 and 5 and entries there against, the following serial number and entries there against shall be substituted, namely:-

"Table

Sr. No.	Nature of power	To whom delegated	Extent
1.	2.	3.	4.
1.	To accept tenders for the execution of all types of works by contract	----	**Up to Rs.25.00 Lakh for each work-**
		(i) Sub Divisional Engineer	subject to the condition that lowest tender amount shall not exceed 5% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.25.00 Lakh.
		(ii) Executive Engineer	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 5% but is upto 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.25.00 Lakh.
		(iii) Superintending Engineer	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.25.00 Lakh.
2.	To accept tenders for the execution of all types of works by contract	----	**More than Rs.25.00 Lakh but upto Rs.1.00 Crore for each work-**
		(i) Executive Engineer	subject to the condition that lowest tender amount shall not exceed 5% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.1.00 Crore.
		(ii) Superintending Engineer	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 5% but is upto 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.1.00 Crore.
		(iii) Chief Engineer	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.1.00 Crore.
3.	To accept tenders for the execution of all types of works by contract	----	**More than Rs.1.00 Crore but upto Rs.3.00 Crores for each work-**
		(i) Superintending Engineer	subject to the condition that lowest tender amount shall not exceed 5% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.3.00 Crores.
		(ii) Chief Engineer	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 5% but is upto 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.3.00 Crores.
		(iii) Tender Allotment Committee consisting of Head of Department as Chairman, Chief Engineers and Chief Accounts Officer as its Members.	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.3.00 Crores.

Sr. No.	Nature of power	To whom delegated	Extent
1.	2.	3.	4.
4.	To accept tenders for the execution of all types of works by contract	----	**More than Rs.3.00 Crores but upto Rs.5.00 Crores for each work-**
		(i) Chief Engineer	subject to the condition that lowest tender amount shall not exceed 5% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.5.00 Crores.
		(ii) Head of Department	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 5% but is upto 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.5.00 Crores.
		(iii) Tender Allotment Committee consisting of Head of Department as Chairman, Chief Engineers and Chief Accounts Officer as its Members.	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.5.00 Crores.
5.	To accept tenders for the execution of all types of works by contract	---	**More than Rs.5.00 Crores but upto Rs.10.00 Crores for each work-**
		(i) Administrative Secretary	subject to the condition that lowest tender amount shall not exceed 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.10.00 Crores.
		(ii) Committee consisting of Minister-in-Charge as Chairman, Administrative Secretary and Head of Department as its Members.	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 10% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.10.00 Crores.
6.	To accept tenders for the execution of all types of works by contract	---	**More than Rs.10.00 Crores but upto Rs.15.00 Crores for each work-**
		(i) Minister-in-Charge	subject to the condition that lowest tender amount shall not exceed 5% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.15.00 Crores.
		(ii) Committee consisting of Chief Minister as Chairman, Minister-in-Charge, Administrative Secretary and Head of Department as its Members.	subject to the condition that lowest tender amount exceeds 5% of the estimated cost of the tender floated with cap of Rs.15.00 Crores.
7.	To accept tenders for the execution of all types of works by contract	Committee consisting of Chief Minister as Chairman, Minister-in-Charge, Administrative Secretary and Head of Department as its Members.	**More than Rs.15.00 Crores for each work-**

Note:- 1. The delegation, as per the table above, shall apply to all Government Departments. All Local Bodies, i.e., Urban Local Bodies and Panchayati Raj Institutions shall have their separate delegations as notified by their respective departments.

2. In the case of Statutory Bodies, Boards and Corporations (except Power Utilities), the Competent Authority for acceptance tenders shall be as per the existing delegation for tenders upto Rs.10 Crore. For works having estimated cost of more than Rs.10 Crore, a Committee consisting of Chief Minister as Chairman, Minister-in-charge, Administrative Secretary and Head (CA, CEO or MD, as the case may be) of concerned Statutory Body, Board or Corporation, shall be the Competent Authority for accepting the tenders.".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Finance Department.

10168—C.S.—H.G.P., Pkl.